

(३५)

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 29 मार्च, 2003

क्रमांक 639 /ब-4/चार/2003/भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राज्य पेशन निधि नियम, 2003" है।  
(2) ये नियम वित्तीय वर्ष 2002-2003 में छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभ :-

ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पेशनभोगियों के प्रति दायित्वों का निर्वहन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पेशन निधि से व्यय से संबंधित मामलों में लागू होंगे।

3. परिभाषा :-

- (ल) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ का राज्य शासन।  
(ख) "निधि" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा स्थापित पेशन निधि।  
(ग) "वित्त विभाग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन का वित्त विभाग।  
(घ) "वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष।

- (2)
- (अ) "पेशन भोगी दायित्व" से अभिप्रेत है, मुख्य शीर्ष - 2071 के अन्तर्गत पेशन दायित्व।
- (ब) "महालेखाकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ का महालेखाकार।

4- राज्य पेशन निधि के संचालन का प्रारंभ :-

राज्य पेशन निधि में राशि का अंतरण एवं संचालन वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होगा।

5- निधि में अन्तरण :-

निधि में निम्न स्त्रोतों से राशि का अन्तरण किया जाएगा :-

- (1) शासन की समेकित निधि से,
- (2) अन्य स्त्रोतों से, जैसा कि शासन समय-समय पर निर्धारित करे।

6- निधि में अन्तरण का निर्धारण :-

- (1) शासन द्वारा किसी एक वर्ष में निधि में अन्तरण की जाने वाली राशि उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में मुख्य शीर्ष-2071-अन्तर्गत पेशनरी दायित्वों पर हुए व्यय के 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगी,

परन्तु, शासन के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथावश्यक इस सीमा से अधिक राशि का अन्तरण किया जा सकेगा।

- (2) अन्य स्त्रोतों से निधि में राशि का अंतरण शासन द्वारा नियम 5(2) के अधीन समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा।

7- निधि का उपयोग :-

इस प्रकार निर्मित निधि का उपयोग वित्त विभाग द्वारा केवल पेशन दायित्वों की पूर्ति के लिए किया जाएगा,

परन्तु वर्ष 2009-10 के पूर्व, निधि में अंतरित राशि का उपयोग किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकेगा।

८. पेशन निधि में जमा राशि का वेष्टन।

(55)

पेशन निधि में उपलब्ध अतिशेष राशि का वेष्टन शासन द्वारा ऐसे वेष्टन के लिये विहित प्रक्रिया अनुसार सिर्फ भारत सरकार शासन की प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

९- निधि का संधारण एवं लेखा :-

पेशन निधि का संधारण वित्त विभाग द्वारा "लोक लेखा" के अधीन किया जाएगा। वित्त विभाग निधि में अन्तरण और प्राप्ति की लेखाओं का संधारण करेगा तथा महालेखाकार से अतिशेष का पुनर्मिलान किया जाएगा।

१०- व्यावृतिः:-

सरकार इन नियमों के उपबंधों के संबंध में निधि के कुशल संचालन तथा प्रशासन के लिये जैसा कि उचित समझे समय-समय पर निर्देश जारी करेगी। इन नियमों के किन्ही उपबंधों के प्रवर्तन में यदि कोई कठिनाई हो तो राज्य सरकार उसका निदान कर सकेगी या नियमों में परिवर्तन कर सकेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(ए.के. बघातसिंह)  
अपर मुख्य सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग